



भारत का राजपत्र The Gazette of India असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1173]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 10, 2010/ज्येष्ठ 20, 1932

No. 1173]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 10, 2010/JYAISTHA 20, 1932

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जून, 2010

का.आ. 1397(अ).—विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 5 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार यह राय होने पर कि ऐसा करना आवश्यक है, यह निर्धारित करने के लिए कि लिबरेशन टाइगर्स आफ तमिल इलम को विधिविरुद्ध संगम घोषित करने के पर्याप्त कारण हैं अथवा नहीं, एतद्वारा, दिल्ली उच्च न्यायालय के पदासीन न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री विक्रमजीत सेन की अध्यक्षता में एक "विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिकरण" का गठन करती है।

[फा. सं. I.11034/1/2010-आई. एस. I]

धर्मेन्द्र शर्मा, उप-सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th June, 2010

S.O. 1397(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government, being of the opinion that it is necessary so to do, hereby constitutes the "Unlawful Activities (Prevention) Tribunal", consisting of Hon'ble Mr. Justice Vikramajit Sen, Judge, Delhi, a sitting Judge of the Delhi High Court for the purpose of adjudicating whether or not there is sufficient cause of declaring the Liberation Tigers of Tamil Eelam as unlawful associations.

[F. No. I.11034/1/2010-IS.I]

DHARMENDRA SHARMA, Jt. Secy.